साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 29 जनवरी-04 फरवरी 2024 वर्ष-9, अंक-41

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

अब किसानों को कैसे मिलेगा मौसम सटीक अनुमान, मौसम विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को भेजा पत्र

देश की 199 जिला कृषि मौसम इकाइयां अप्रैल में होंगी बंद

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां अब बंद होने जा रही हैं। देशभर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित इन इकाइयों को 31 मार्च के बाद यानी अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। दो दिन पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। जिला कृषिमौसम इकाइयों की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) और भारत मौसम विज्ञान विभाग के बीच वर्ष 2019 में हुए करार (एमओयू) के बाद की गई थी। हालांकि, फरवरी 2022 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस योजना को 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन समय से पहले ही वित्त विभाग की अनुशंसा पर इन इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के पीछे आर्थिक तंगी बड़ी वजह मानी जा रही है।

मप्र के 13 जिलों में इकाइयां

मध्य प्रदेश के 13 जिलों में जिला कृषि मौसम इकाई संचालित हो रही हैं, जो मार्च के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इनमें बालाघाट, कटनी, रीवा, शहडोल, छतरपुर, दमोह, सिंगरौली, गुना, खंडवा, शिवपुरी, राजगढ़, अशोकनगर और बड़वानी शामिल हैं। मप्र की ये इकाइयां जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा संचालित हो रही थीं।

वेतन के पड़े लाले | देश के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित प्रत्येक इकाई में दो कर्मचारी (एक कृषि विज्ञानी और एक आब्जर्वर) संविदा पर नियुक्त किए गए थे। देशभर में करीब 400 कर्मचारियों को वेतन के लिए सात से आठ महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब इनके सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है।

वेतन विवि दे रहे थे

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत बालाघाट, कटनी, रीवा, शहडोल, छतरपुर, दमोह, सिंगरौली की इकाइयां, तो ग्वालियर के विश्वविद्यालय के अधीन गुना, खंडवा, शिवपुरी, राजगढ़, अशोकनगर और बड़वानी की इकाइयां शामिल हैं। यहां के कर्मचारियों का वेतन विवि द्वारा दिया जा रहा था।

इस संबंध में भारत मौसम विज्ञान विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। इकाइयां क्यों बंद की जा रही हैं, ये स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि इकाइयों को नए सिरे से या कुछ बदलावों के साथ दोबारा शुरू किया जा सकता है।

आरएल राउत, वरिष्ठ वैज्ञानी व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव

लैब से टेस्टिंग के बाद परोसा जाएगा मांस

मप्र में गिद्धों के लिए बनेगा वल्चर रेस्टोरेंट

» संरक्षण के लिए कार्य अप्रैल माह से शुरू होगा

» फिलहाल टाइगर रिजर्व में सात प्रजाति के गिद्ध

भोपाल। जागत गांव हमार

नौरादेही अभयारण्य को मिलाकर बनाए गए रानी दुर्गावती टाईगर रिजर्व को देश के सबसे बड़े टाईगर रिजर्व की पहचान मिली है। क्योंकि इसकी कुल लंबाई 2300 वर्ग किमी है और पांच साल में यहां बाघों की संख्या 19 पहुंच गई है। अब यहां भारत से विलुप्त हो रही गिद्धों की प्रजाति को बढ़ाने के लिए नया प्रयास शुरू हो रहा है।

यहां वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है आने वाले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत तीन जिले पहले से शामिल हैं जिसमें सागर, नरसिंहपुर और दमोह जिला शामिल है। दमोह जिले के तेंदूखेड़ा और जबेरा जिसका जंगली भाग सामान्य वन क्षेत्र में आता था उसको मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसकी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अभी क्षेत्र हैंडओवर नहीं हुआ है।

यहां बनाए जाएंगे रेस्टोरेंट

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट के लिए तीन जगह चिन्हित की गई हैं। जिसमें नरसिंहपुर जिले के डोगरगांव में दो जगह जबकी तीसरा स्थान नौरादेही का मोहली होगा। यहां पर दो हेक्टेयर क्षेत्र को तार से घेरकर एक बाड़ा बनाया जाएगा। जिसमें मृत मवेशियों के मांस का परीक्षण करने के बाद गिद्धों को मांस परोसा जाएगा। जिसके बाद इन स्थानों पर गिद्धों की सख्या और बढ़ने लगेगी। मांस को देखकर ही गिद्ध एकत्रित होते हैं यदि प्रयास सफल रहा तो टाइगर रिजर्व में गिद्धों की तादाद कुछ ही वर्षों में दोगनी या तीन गुनी हो सकती है।

यह है गिद्धों की स्थिति

कभी गिद्ध भारत की पहचान होते थे, लेकिन धीरे- धीरे इनकी संख्या घटने लगी और नौबत ये आ गई कि गिद्ध प्रजाति भारत से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। बात मध्यप्रदेश की करें तो पूरे मप्र में गिद्ध दस हजार से ऊपर ही बचे हैं। ऐसी स्थिति में गिद्धों को बचाने के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में यह प्रयास उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा और उन्होंने इस अभियान को शुरू करने की मंजूरी दे दी। 2021 में यदि नोरादेही अभ्यारण में गिद्ध गणना की बात करे तो यहां मात्र 300 गिद्ध थे, लेकिन उसके बाद इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

यहां से आएगा मांस

टाइगर रिजर्व में गिद्धों की प्रजाति बढ़ाने के लिए जो प्रयास शुरू हो रहे हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में मवेशियों के मांस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि गिद्धों का मुख्य आहार मवेशियों का मांस है। इसलिए टाइगर रिजर्व के अधिकारी गौशालाओं से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां प्रतिदिन मवेशियों की मौत होती है जिनको गौशाला संचालक जमीन के नीचे दफना देते हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारी अब उन मवेशियों को दफनाने की जगह लैब भेजेंगे। मृत मवेशियों के मांस का पहले परीक्षण होगा यदि वह मांस सही निकला तो उसको उस रेस्टोरेंट में रखा जाएगा उसके बाद उस मांस को गिद्धों को परोसा जाएगा।

अप्रैल महीने में शुरू होगा कार्य

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण के लिए यह कार्य अप्रैल माह से शुरू होगा। जिन स्थानों पर यह मांस गिद्धों को परोसा जाएगा उन स्थानों को भी सुरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व में सात प्रजाति के गिद्ध हैं। उसमें वह प्रजाति भी शामिल है जो लुप्त होने की कगार में है। टाइगर रिजर्व में पदस्थ अधिकारियों का मानना है कि यह प्रयास सफल होता है तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भविष्य में गिद्धों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती।

बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डारेक्टर अब्दुल अंसारी ने बताया कि पूर्व में हमारे भारत में गिद्धों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व डाइको फिनाक नामक दवा आई थी। यह दवा मवेशियों को बुखार आने पर दी जाती थी, लेकिन जब मवेशियों की मौत हुई और उनके मांस को गिद्धों ने खाया तो उनकी मौत होती गई। नौबत यह आ गई कि गिद्ध की प्रजाति लुप्त होने की कगार में पहुंच गई। जिनको बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जिसके लिए वल्चर रेस्टोरेंट बनाकर गिद्धों की प्रजाति बढ़ाने का प्रयास शुरू हो रहे हैं। पूर्व में यही प्रयास नेपाल और महाराष्ट्र में किया गया था जो सफल रहा, इसलिए अब यही प्रयास वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अप्रैल माह से शुरू किया जा रहा है।

भोपाल की टीम ने 35 हजार क्विंटल धान की रिजेक्ट

» एडीएम ने बैठाई जांच, अब दोषियों पर गिरेगी गाज

कटनी। मध्यप्रदेश के कटनी जिले में विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से उपार्जन केन्द्रों में खरीदी प्रभारी और समिति प्रबंधकों ने बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की धान खरीद डाली और उसे भंडारण के लिए वेयरहाउस भेजा गया। हालांकि पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ, जब भोपाल की सर्वे टीम लगातार 4 दिनों में अलग अलग तहसीलवार बने वेयरहाउस के बाहर ही ट्रकों को रोककर धान की गुणवत्ता की जांच करते हुए उसे रिजेक्ट करार दे दिया। जिसके बाद से ही खरीदी में शामिल पूरे विभागों में हड़कंप मचा और आनन-फानन में जिला प्रशासन ने एक टीम गठित कर रिजेक्ट धान की जांच के लिए भेजा, जिसे उन्होंने भी घटिया किस्म की धान मिलने पर सैंपल फेल कर दिए। इधर, एडीएम साधना परस्ते ने बताया कि धान की जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम पिछले 16 दिसंबर से अलग अलग जा रही थी। वहीं 7 जनवरी को खुद एडीएम अन्य विभागीय अधिकारियों के दल बल के साथ पहुंची थी, जिन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की धान पकड़ी थी।

14 जनवरी से कटनी पहुंची

भोपाल की सर्व टीम आरबी एसोसिएट की जो 14 जनवरी से कटनी पहुंची और धान की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए करीब 35 हजार क्विंटल धान रिजेक्ट की है। हालांकि इसमें से अधिकांश धान को अपग्रेड कराया गया है, लेकिन रिजेक्ट हुई धान विजयराघवगढ़, बड़वारा, बहोरीबंद, उमरियापान सहित अन्य समितियों के अंदर आने वाले खरीदी केंद्रों की बताई गई है। इस पूरे मामले की जांच गठित टीम से करवाई जा रही है, जिसमें दोषियों के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्रवाई की जाएगी।

कुछ महीनों के बाद होगी सोयाबीन की बोवनी, किसानों को पांच सवालों में पूरी जानकारी

फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रजातियों के अच्छे बीज का उपयोग बहुत जरूरी

मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र की जलवायु सोयाबीन के लिए काफी अनुकूल

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन एक तिलहन फसल है। सोयाबीन देश में कुल तिलहन फसलों का 42 प्रतिशत और कुल खाद्य तेल उत्पादन में 22 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। इसमें प्रोटीन 40 प्रतिषत एवं वसा 20 प्रतिशत होने के कारण यह पोषण का एक प्रभावी माध्यम है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जलवायु सोयाबीन के लिए काफी अनुकूल है। यह दोनों राज्यों की प्रमुख खरीफ फसलों में से एक है। कुछ ही समय में इसकी खेती शुरू होने वाली है। इसलिए किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास बात यह है कि इसकी खेती हल्की व रेतीली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की जमीन में सफलतापूर्वक की जा सकती है। कई बार इसका बहुत अच्छा दाम मिलता है। इसलिए दोनों राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले किसान पांच सवालों का जवाब जरूर जान लें।

सवाल: सोयाबीन की बोवनी का सही समय क्या है?

जवाब: सोयाबीन की बोवनी जून के अंतिम सप्ताह में सर्वोत्तम होती है। बोवनी के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन मे पर्याप्त मात्रा में नमी हो। मानसून आने पर लगभग 4-5 इंच वर्षा होने के बाद अंकुरण व बाद के फसल विकास के लिए जमीन में पर्याप्त नमी हो जाती है। वायुमंडल एवं मृदा का तापमान 28-30 डिग्री सेन्टीग्रेड होने से फसल का विकास अच्छा होता है। 15 जुलाई के बाद सोयाबीन की बोवनी लाभप्रद नहीं होती है।

सवाल: सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?

जवाब: सोयाबीन फसल के लिए खेत की तैयारी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गहरी काली मिट्टी वाले खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था हो। गर्मी की गहरी जुताई हर तीसरे वर्ष 9 से 12 इंच गहराई तक करना चाहिए। इससे गर्डल बीटल के प्यूपा तथा अन्य कीट और फफूंद गर्मी में खुले खेत में ही नष्ट हो जाएंगे।

सवाल: सोयाबीन की बोवनी के लिए बीज का चयन कैसे करें?

जवाब: फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रजातियों के अच्छे बीज का उपयोग बहुत जरूरी है। हमेशा सर्टिफाइड जगह से बीज खरीदिए, ताकि उसमें जमाव अच्छा हो। खरीद के बाद रसीद जरूर ले लें। जिससे कि बीज खराब होने के बाद उस पर क्लेम किया जा सके। सोयाबीन फसल की बोवनी के लिए कतार से कतार की दूरी 30-45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर रखें।

सवाल: सोयाबीन की बोवनी के लिए बीज दर क्या रखनी चाहिए?

जवाब: सोयाबीन की बोवनी के लिए दानों के आकार के अनुसार 30-40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ या 15-20 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। बीज के साथ किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ या 5 बीघा होगा।

सवाल: सोयाबीन फसल मे बीजोपचार कैसे किया जाता है?

जवाब: सोयाबीन फसल मे बीजोपचार करने की एक विधि होती है। जिसका नाम एफआईसी है। सर्वप्रथम फफूंनाषक मे विटावेक्स पावर/अल्ट्रा 2 ग्राम या 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलो बीज के मान से भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद राईजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर एवं ट्राईकोडर्मा 5 ग्राम प्रत्येक से 1 किलो बीज उपचारित किया जाता है। इन कवक नासियों से उपचारित बीज को छाया में सुखाकर ही बोवनी करनी चाहिए।

पतंजलि के वैज्ञानिकों की टीम 50 हजार औषधीय पौधों की खोज कर उसका प्रलेखीकरण भी किया

मध्य प्रदेश में औषधीय गुण वाले 33 पौधों पर रिसर्च

-11 राज्यों से आए 25 वैज्ञानिकों ने पौधों पर दिए व्याख्यान

-शोध में ऐसे पौधे भी शामिल, जिनकी पहचान नहीं हो सकी

भोपाल। जागत गांव हमार

आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, यानी यह कई संस्कृतियों के इतिहास से पुराना है। लेकिन इसे बीच-बीच में लोग इसे भूलते रहे। मुगल शासक आए तो यूनानी का प्रभाव बढ़ा। जब अंग्रेज आए तो एलोपैथी का असर बढ़ गया। लेकिन अब फिर लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया आयुर्वेद को वापस मान रही है। यह बात हेड पतंजलि रिसर्च की वेद प्रिय आर्य ने पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही।

11 राज्यों से आए प्रतिनिधि: भारतीय आयुर्वेदीय भेषज संहिता की समृद्धि के लिए

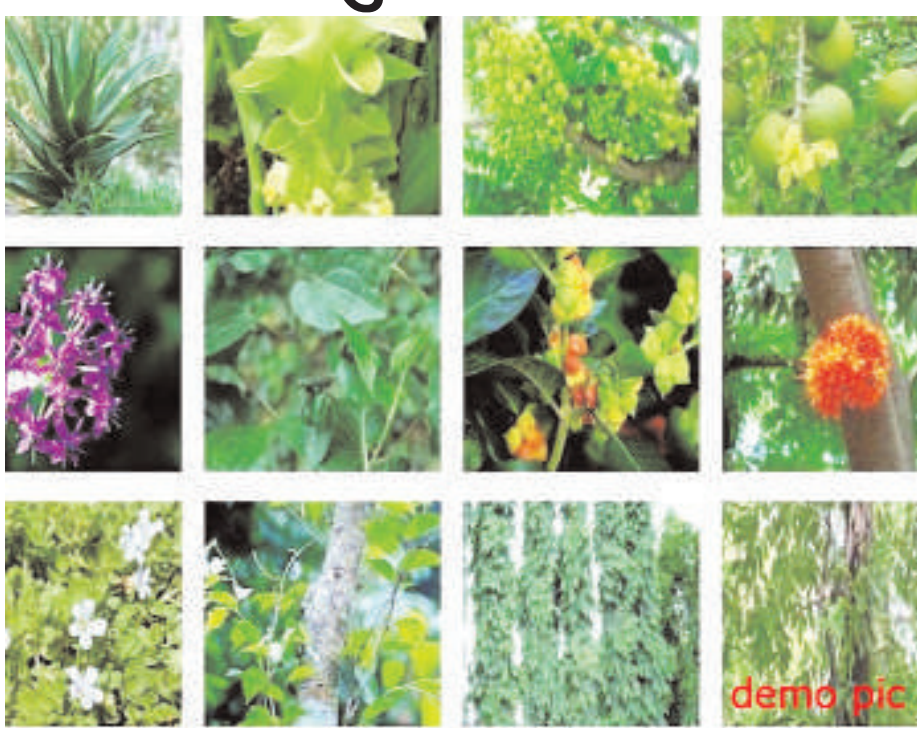

वानस्पतिक प्रजातियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं प्रलेखीकरण को लेकर आयोजित कार्यशाला के दौरान वेद प्रिय आर्य ने बताया कि पतंजलि के वैज्ञानिकों की टीम 50 हजार औषधीय पौधों की खोज कर उसका प्रलेखीकरण भी किया है। जिसमें लगभग विश्व के सभी औषधीय पौधे शामिल है। भारत में आयुर्वेद रिसर्च का काम तेजी से बढ़ा है। पतंजलि ने इकलौती चेकलिस्ट बनाई है जो यह बताती है कि देश और दुनिया में करीब 50 हजार औषधीय पौधे हैं। इनमें से कुछ पर रिसर्च चल रही है। इस दौरान 11 राज्यों से आए 25 से अधिक वैज्ञानिकों ने औषधीय पौधों को लेकर व्याख्यान दिए।

जनजातीय क्षेत्रों में हो रही रिसर्च

मध्यप्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से 33 ऐसे औषधीय पौधे पर रिसर्च किया जा रहा है। इसमें से पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल के चिकित्सक काम कर रहे हैं। इसमें से विभाग को 25 औषधीय पौधों की पहचान नहीं हो सकी है। जिस पर काम किया जा रहा है। डॉ. अंजली जैन ने बताया कि यह सभी पौधे ट्राइबल क्षेत्र के हैं। जोकि डिंडोरी, शहडोल, मंडला और अनूपपुर जिले से मंगाई गई है।

किसानों को आत्मनिर्भर बनने जतन कर रही सरकार, सरसों की खेती का दायरा बढ़ना देश के लिए राहत

पैसा इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना और मोजांबिक जैसे देशों के किसानों की जेब में जा रहा

पिछले पांच साल में बढ़ा दलहन और तिलहन फसल का उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

दलहन और तिलहन फसलें लंबे समय से भारत में उपेक्षित रही हैं। हमारे नीति निर्धारकों ने भारत में खेती बढ़ाने की बजाय आयात का रास्ता अपनाया। नतीजा यह हुआ कि आज हम इन दालों और खाद्य तेलों को मिलाकर 1 लाख 58 हजार करोड़ रुपए से अधिक रकम खर्च कर रहे हैं, जो धान-गेहूं एक्सपोर्ट करके कमाते हैं उससे अधिक हम इन दोनों पर खर्च कर देते हैं, जो पैसा भारतीय किसानों को मिलना चाहिए वो पैसा इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, म्यांमार और मोजांबिक जैसे देशों के किसानों की जेब में जा रहा है। सिर्फ पॉलिसी ठीक न होने की वजह से, लेकिन, अब वर्तमान सरकार की स्पष्ट सोच है कि इन दोनों फसलों की आयात निर्भरता खत्म करके हमें इनमें आत्मनिर्भर बनना है। पिछ कुछ वर्षों से इस पर काम हो रहा है और उसका नतीजा भी बढ़े उत्पादन के तौर पर दिखाई दे रहा है।

सरकार का दावा-अब उत्पादन 413.55 लाख मीट्रिक टन

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में तिलहन फसलों का उत्पादन 315.22 लाख मीट्रिक टन था जो 2022-23 में बढ़कर 413.55 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी मोटे तौर पर पांच साल में हमने 98 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ा लिया है। सरकार अब इसे और बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि यह रफ्तार तेज तब होगी जब सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों का किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। जैसा कि कोराना काल के समय और उसके बाद के दो साल तक मिला है।

दलहन फसलों का उत्पादन

अगर बात करें दलहन फसलों के उत्पादन की तो 2018-19 में भारत सिर्फ 220.75 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करता था, जो 2022-23 में बढ़कर 260.59 लाख टन हो गया। इसका मतलब कि पिछले पांच साल में करीब 40 लाख टन की वृद्धि हुई है। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया की करीब 25 फीसदी दालें यहीं पैदा होती हैं, लेकिन खपत दुनिया की 28 फीसदी होती है। इसलिए हम अब भी आयातक हैं। सरकार ने दिसंबर 2027 तक दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो दलहन की खेती करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन करके दलहन की शत-प्रहतशत खरीद करेगी।

तिलहन के लिए कोशिश

केंद्र तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन संचालित कर रहा है। तिलहन फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, नाइजर, अलसी और अरंडी आते हैं। सरकार ने ऑयल पाम क्षेत्र का विस्तार करके खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। इस मिशन के तहत 2025-26 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर ऑयल पाम रोपण होगा। यह मिशन देश के 15 राज्यों में लागू है।

दलहनी फसलों के रकबे में कमी

इधर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रबी दलहन फसलों का कुल उत्पादन क्षेत्र 7.53 लाख हेक्टयर घट गया है। पिछले साल के 162.66 लाख हेक्टेयर से घटकर इस बार 155.13 लाख हेक्टेयर रह गया है। चना, उड़द, और मूंग का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसी साल खरीफ सीजन में दलहन का क्षेत्र 5.41 लाख हेक्टेयर से कम हो गया है। इस घटे हुए रकबे के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ सकता है, यानी इससे देश में दाल को बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ सकता है, जबकि सरकार दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रही है ताकि साल 2027 तक भारत दाल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

किसानों का मोटे अनाजों की ओर रुख

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के निदेशक, डॉ. पीजी दीक्षित ने कहा कि दलहनी फसलों की मुख्य रूप से वर्षा आधारित जमीनों में खेती होती है। इस खरीफ मौसम में कम बारिश के कारण दक्षिण के राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, सहित मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों का क्षेत्र कम हो गया है। वैसे ही, रबी मौसम में अक्टूबर में कम वर्षा के कारण खेतों में नमी की कमी हो गई है, जिससे मुख्य रूप से चना के क्षेत्र महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में काफी कम हो गया है। दलहन और मोटे अनाजों की खेती सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती है और इन क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती में प्रोत्साहन मिलने से किसानों ने मोटे अनाजों की ओर रुख किया है।

खंडवा के किसान ने खेत को बनाया प्रयोगशाला, पटेल से प्रेरणा लेकर कई किसानों ने बढ़ाया उत्पादन

स्वयं के खर्च पर 54 हजार वर्गफीट में बनवाया तालाब

प्याज बीज उत्पादन कर मध्य प्रदेश में बनाई पहचान

खंडवा। जागत गांव हमार

जिले के ग्राम भगवानपुरा के युवा उन्नतशील किसान पंकज कड़वाजी पटेल ने बीज उत्पादन क्षेत्र में पूरे प्रदेश में पहचान बनाई है। उन्होंने अपने खेत को प्रयोगशाला बनाया है और वर्ष 2009 से प्याज के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। पंकज 15 से 20 एकड़ में प्याज लगाते हैं, जिससे 25 से 30 मजदूरों को रोजगार मिलता है। इससे प्रेरित होकर अन्य किसान भी अपने खेत में प्रयोग कर लाभ कमा रहे हैं। पंकज के खेत पर कई जिलों के किसान विजिट करने आते हैं, जिनमें हरदा, उज्जैन, देवास, धार, बड़नगर, बदनावर, सीहोर के कृषक शामिल हैं। पटेल सभी किसानों के साथ उच्च उत्पादकता के बीज शेयर करते हैं। ताकि किसानों को अच्छा उत्पादन मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

कृषि वैज्ञानिक से प्रेरणा ली

पटेल बताते हैं कि कृषि वैज्ञानिक डॉ. देवेंद्र पासी से प्रेरणा पाकर उन्होंने इस बीज को चुना। वजह प्याज बीज उत्पादन करना एक कठिन विधा है। इसमें किसान का कौशल होना अतिआवश्यक है, क्योंकि प्याज एक हाईली क्रास पोलिनेटेड क्राप है। इसमें परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, इसमें किसान को बहुत सावधानीपूर्वक रसायनों का इस्तेमाल करना होता है, इनमें सिर्फ उन्हीं रसायनों का उपयोग होता है, जो हनी बी फ्रैंडली हो। मौसम वैज्ञानिक डॉ. सौरभ गुप्ता के अनुसार बेहतर खेती के लिए किसानों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सलाह दी जाती है, जिसका अनुसरण कर किसानों की लागत में 25 प्रतिशत तक की कमी आई है।

बीज उत्पादन तकनीक को मिली सराहना

जवाहर लाल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2020 में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में पंकज पटेल द्वारा प्याज बीज उत्पादन तकनीक पर अपना प्रेजेंटेशन दिया गया। इसे विज्ञानियों ने सराहा है। पटेल पानी के महत्व को समझते हैं। इसलिए जल है तो कल है के सूत्र पर चलते हुए पटेल ने अपने खेत पर 54 हजार वर्गफीट में एक विशाल तालाब का निर्माण स्वयं के खर्चे पर करवाया है। इसमें वह अमूल्य वर्षा जल का संचय कर उसं कृषि में उपयोग करते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी गहराई से आता है। इसका टीडीएस लेवल काफी हाई होता है, जो भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करता है, इसलिए पटेल संचयित जल का ही उपयोग करते हैं।

बड़े एरिया में प्याज बीज उत्पादन

पटेल कृषि में लगने वाले बीज के महत्व को समझते हैं इसलिए किसानों को उत्तम प्रजाति के बीज प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने खेत को कृषि प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया है। पटेल के पास चना, गेहूं तथा प्याज की उत्तम क्वलिटी और अधिकतम उत्पादन देने वाली किस्में हैं। चना में पूसा मानव, आरवीजी 205, हिट और ड्राउट टालरेंट अबीजीएम 10216, गेहूं में एचआइ 1650, एचआइ 1655, एमएसीएस 6768, डीबीडब्लू 327 सहित पटेल के पास गेहूं की सीजी 1036 वैरायटी भी है, जिसका चपाती सूचकांक 8.50 है, जो शरबती गेहूं से भी अधिक है। पंकज मार्केट रेट से कम दाम में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराते हैं। मध्य भारत में सबसे बड़े एरिया में प्याज बीज उत्पादन करते हैं।

पुस्तक समीक्षाः कृषि की उन्नत तकनीकियां (चुनौतियां और सुझाव)

लेखकः डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) म.प्र.

आधुनिक भारत में खेती किसानी का बहुत अधिक विकास हुआ है। नितरोज नई कृषि उन्नत तकनीकियां आ रही हैं। नवीनतम कृषि उन्नत तकनीकियों से आधुनिक कृषि को मजबूती मिली है। खेती किसानी में विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों से लेकर अनेकों उन्नत कृषि यंत्र भी आज चलन में हैं। इन सब का लाभ खेती किसानी में किसानों को मिला है। फसलों के उत्पादन के साथ ही पशुओं की उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। लेकिन बावजूद इसके आज भी खेती किसानी से लेकर पशुपालन के सामने कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

फसलों में रोग कीट एवं खरपतवारों की समस्या के साथ ही उन्नत किस्म की उपलब्धता की कमी बनी हुई है। किसानों का सहायक व्यवसाय पशुपालन भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। पशुपालन करने वाले किसानों के सामने महंगे चारे-दाने से लेकर अच्छे और सस्ते इलाज की उपलब्धता न होना प्रमुख चुनौतियों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पशुओं की नस्ले विलुप्त हो रही हैं। एक तरफ जहां विश्व के नंबर एक दूध उत्पादक देश में और अधिक दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने की संभावनाएं विद्यमान हैं। वही फसलों, सब्जी और फलों के उत्पादन को भी और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रचुर संभावनाएं अभी भी विद्यमान है। लेकिन इन सबके उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाए जाने के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

खेती किसानी एवं पशुपालन के समक्ष आज जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग हर मौसम में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां खेती किसानी को हानि पहुंचा रही है। कम वर्षा, असमान वर्षा, वर्षा के दिनों में कमी, कुछ ही दिनों में बहुत अधिक बरसात हो जाना तथा बाद के दिनों में फिर सूखा पड़ना जलवायु परिवर्तन की जैसी चुनौतियों के कारण ही पैदा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण साल दर साल तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है। इन सब चुनौतियों को मध्ये नजर रखते हुए कृषि में उन्नत तकनीकियों को आगे बढ़ाना होगा। जलवायु अनुकूल तकनीकी को अपनाने के लिए किसानों को तत्पर होना होगा। वही वैज्ञानिकों को भी जलवायु अनुकूल तकनीकियां विकसित करनी होगी जिससे किसानों को उनका लाभ मिल सके। आधुनिक उन्नत कृषि में आज एक बार फिर प्राकृतिक खेती की भी चर्चा हो रही है। प्राकृतिक कृषि को भविष्य की कृषि कहा जा रहा है। वही मोटे अनाज भी भविष्य के अनाज के रूप में देखे जा रहे हैं। इस दिशा में किसानों व सरकारों द्वारा भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले समय में उन्नत कृषि में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होगा।

इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधीन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह द्वारा कृषि की उन्नत तकनीकियां (चुनौतियां और सुझाव) विषय पर नवीनतम ज्ञान को समेटे पुस्तक लिखी है। राठौर एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कुल 235 पेज तथा 36 अध्याय शामिल हैं। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा वर्ष 2021 से लेकर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म पर अपने द्वारा लिखे गए प्रकाशित लेखों को संकलित कर पुस्तक का रूप दिया है।

प्रस्तुत पुस्तक कृषि की उन्नत तकनीकियां (चुनौतियां और

सुझाव) मैं लेखक द्वारा कृषि बने लाभ का व्यवसाय, जलवायु परिवर्तन से पशुपालन के क्षेत्र में भी बढ़ रही है गंभीर चुनौतियां, कृषि तकनीकी को किसने तक पहुंचने वाले कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम करते हैं, सुपर फूड बनते मोटे अनाजों को थाली और खेत में वापस लाने की जरूरत, पानी की बर्बादी रुकेगी तभी होगा जल संकट का समाधान, कुपोषण से जंग लड़ने में कितनी मददगार साबित होगी बायो फोर्टीफाइड किस्में, देश के किसानों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा प्राकृतिक खेती का भविष्य, प्रकृति का बदलता मिजाज किसानों पर पड़ रहा भारी, जी एम सरसों से तेल में आत्मनिर्भरता की दरकार, कीटनाशकों के विकल्प की जरूरत, मोटे अनाजों में छुपा है पोषण का खजाना, बदलते गांव ग्रामीण भारत की बदलती जीवन शैली, तपती धरती और बढ़ता अनाज का संकट, पर्यावरण संतुलन क्यों है खेती के लिए चुनौती, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकी की जरूरत आदि विषयों पर सारगर्भित जानकारियां समेटे हुए प्रस्तुत पुस्तक में उनसे आने वाली चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की गई है। प्रस्तुत पुस्तक मैं कृषि की उन्नत तकनीकियों के साथ ही भारत सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई है। यह पुस्तक किसानों के साथ ही कृषि अध्ययन करने वाले स्नातक एवं परा स्नातक छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

लेखक डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह विगत 29 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर किसानों की सेवा में अनवरत रूप लगे हुये हैं। डॉ. सिंह के अब तक 55 से अधिक शोध पत्र 300 से ऊपर व्यावहारिक लेख, दर्जनों तकनीकी फोल्डर, बुकलेट, कृषि पशुपालन से जुड़े साहित्य के अलावा समसामयिक विषयों से लेकर खेती-बाड़ी स्वदेशी, प्राकृतिक कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर लेख एवं संपादकीय विभिन्न प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. सिंह को अब तक के अपने सेवा काल में कई पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना में अच्छे कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया अवार्ड-2016 तथा श्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र आउटलुक स्वराज अवार्ड-2020 से तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्रीगण, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर डॉ. सिंह युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार, पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार, श्रेष्ठ लेखक सम्मान, विशिष्ट वक्ता पुरस्कार के अलावा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित दर्जनों पुरस्कारों से विभिन्न संस्थानों एवं संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं।

अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है मोक्षदायिनी क्षिप्रा

अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही मध्यप्रदेश की 'मोक्षदायिनी' क्षिप्रा नदी के लिए राज्य की नई सरकार ने एक योजना की घोषणा की है। इसके तहत क्षिप्रा के प्रदूषण के लिए घोषित जिम्मेदार कान्ह (खान) नदी को उज्जैन शहर से बाहर ले जाना है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे उज्जैन शहर में बहने वाली क्षिप्रा तो साफ हो सकती है, लेकिन आगे जाकर कान्ह फिर से क्षिप्रा नदी में मिलकर प्रदूषित करेगी।

इंदौर जिले के ग्राम मुण्डलादोस्तदार से निकली क्षिप्रा नदी 195 किमी का सफर तय कर रतलाम जिले में शिपावरा नामक स्थान पर चम्बल नदी में मिल जाती है। इस नदी को मध्यप्रदेश की गंगा भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इसके किनारे समय बिताने और स्नानादि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी नदी के किनारे उज्जैन में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुम्भ का आयोजन होता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर यहीं स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में स्नान अवश्य करते है, विशेषकर तीज-त्यौहारों पर यहां स्नान के लिये बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब क्षिप्रा पहले जैसी नहीं रही। नदी के उद्गम स्थल मुंडलादोस्तदार गांव से संगम स्थल उज्जैन तक इन दिनों बूंद भर पानी नहीं है। मुण्डला दोस्तदार के निकट सूखे पड़े प्रवाह मार्ग पर कुछ जगह कांक्रीट की पक्की नहर बना दी गई है, ताकि उसमें लिफ्ट कर डाला गया नर्मदा का पानी बहाया जा सके। क्षिप्रा में प्रदूषण का बड़ा कारण कान्ह नदी को बताया जाता है। कान्ह भी कभी नदी रही है लेकिन फिलहाल तो वह लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ घोषित शहर इंदौर के सीवरेज और रास्ते में पने वाले औद्योगिक अपशिष्टों की वाहक मात्र है। साल 2016 के सिंहस्थ कुम्भ के दौरान क्षिप्रा नदी में जल उपलब्धता हेतु 432 करो की नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना का 2014 में शिलान्यास किया गया था। इस योजना के तहत नर्मदा नदी का पानी 2 बार लिफ्ट कर के ग्राम सजवाय लाया गया और नहर के माध्यम से इसे क्षिप्रा गांव में नदी में मिलाया गया। सजवाय गांव से ही एक छोटी पाइप लाइन मुण्डला दोस्तदार ग्राम की ककी-बली पही पर स्थित एक क्षिप्रा मंदिर तक पहुंचाई गई है। इस मंदिर के सामने एक छोटा से कुण्ड, जिसे क्षिप्रा का उद्गम स्थल बताया जाता है, को नर्मदा जल से भरा जाता है। 6 जनवरी 2024 को इस प्रतिनिधि ने पाया कि मुण्डला दोस्तदार की ककडी-बली पही पर क्षिप्रा मंदिर के सामने का उदगमकुण्ड सूखा पा था। पही के नीचे सरकार ने करोंों रुपये खर्च कर वाटर पार्क बनाया है जहां इस समय पानी सा हुआ है और उसमें जलीय खरपतवार पनप रही है। वाटर पार्क में छुट्टी के दिनों में शहरी लोग तफरीह के लिए आते हैं और गन्दगी फैला जाते हैं। क्षिप्रा मंदिर के पुजारी के बेटे रजत शर्मा बताते हैं कि पानी की मोटर खराब हुए एक महीने से अधिक हो गया है। कई बार सम्बंधित अधिकारियों को सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उज्जैन शहर के दक्षिण में स्थित त्रिवेणीघाट पर क्षिप्रा नदी में इंदौर से आने वाली प्रदूषित कान्ह नदी मिलती है। कान्ह नदी को क्षिप्रा के प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तीज-त्यौहारों के अवसर पर कान्ह नदी को क्षिप्रा में रोकने के लिए त्रिवेणी घाट पर मिट्टी का अस्थाई बांध बनाने की कवायद की जाती है। नर्मदा के साफ पानी को गंदा होने से बचाने के लिए नरसिंह घाट से आगे के घाटो का प्रदूषित पानी खाली कर दिया जाता है। इसके बाद क्षिप्रा गांव के डेम से नर्मदा का जल छोा जाता, जो 8 से 10 घण्टों में उज्जैन स्थित क्षिप्रा में पहुंचता है स्नान-आचमन के बाद मोटर पंप बंद कर दिए जाते हैं। त्रिवेणी संगम स्थित कान्ह नदी पर बनाया अस्थाई बांध प्रदूषित पानी के ओवरफ्लो होने से कुछ दिनों में टूट जाता है और क्षिप्रा नदी फिर से पहले जैसी प्रदूषित हो जाती है। क्षिप्रा को कुछ दिनों के लिए साफ दिखाने

की यह प्रक्रिया साल भर चलती रहती है जिसे सरकार, साधु-संत, श्रध्दालु और आम नागरिक सभी ने सहज रुप से स्वीकार कर लिया है।

7 जनवरी 2024 को इस प्रतिनिधि ने उज्जैन के रामघाट पर देखा, नहाने वालों की संख्या बहुत कम थी और नदी में गन्दगी साफ नजर आ रही थी। इसी दिन त्रिवेणीघाट पर क्षिप्रानदी में भरा पानी खाली किया गया था। क्षिप्रा का नदी तल जलीय खरपवार से भरा पा थे और चारों ओर दुर्गंध का सामाज्य था। कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को रोकने के लिये डम्परों व जेसीबी की सहायता से पास में ही मिट्टी का अस्थाई बांध बनाया जा रहा था ताकि मकर सक्रांति के दिन स्नान संभव हो सके। क्षिप्रा की तरह इंदौर की कान्ह नदी की सफाई के नाम पर भी सिर्फ पैसा बहाया जा रहा है। विगत 15 सालों में इस नदी पर 1,157 करो रुपये खर्च करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना से हाल ही में 598 करो रुपये फिर से स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि का उपयोग कान्ह नदी को डायवर्ट करने, स्टापडेम बनाने, जल उपचार संयंत्र स्थापित करने में किया जाएगा। बांधों, नदियों और लोगों पर दक्षिण एशिया नेटवर्क (सेंड्रप) के समन्वयक हिमांशु ठक्कर बताते हैं कि एक नदी से पानी लाकर दूसरी में प्रवाहित किया जाना तकनीकी रुप से संभव तो है लेकिन वित्तीय दृष्टि से अत्यंत महँगा होने के कारण भारत जैसे तीसरी दुनिया के गरीब देशों के लिए यह तरीका कारगर नहीं है। प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षमता पर सवाल खा करते ठक्कर कहते हैं कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुए 50 साल हो गये है। इस बोर्ड की इकाईयां राज्यो में काम करती है। लेकिन इस बोर्ड ने आज तक किसी एक छोटी सी भी जल संरचना या नदी को साफ किया हो करवाया हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। वह बताते हैं कि यह बोर्ड सरकार के अधीन काम करता है जिसका अपना कोई बुनियादी ढाँचा नहीं है। इसके अपने न तो कोई लक्ष्य निर्धारित हैं और न ही इसकी कोई जवाबदेही है। इसके क्रियाकलाप में पारदर्शिता भी नहीं है ऐसे में इससे किसी जल संरचना के प्रदूषण मुक्त करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं वे कहते हैं कि स्वायत्तता देकर ही इससे कोई उम्मीद की जा सकती है। योगमठ उज्जैन के अध्यक्ष पण्डित योगाचार्य जयवर्द्धन भारद्वाज के अनुसार उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालु अब क्षिप्रा स्नान की बजाय महाकाल मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2028 के सिंहस्थ के पहले मुख्यमंत्री क्षिप्रा शुद्धिकरण योजना में सफल होंगे क्योंकि वे स्वयं उज्जैन से हैं और क्षिप्रा की दुर्दशा से परिचित हैं।

साभार

अब जरूरी है पर्यावरण के लिए जारगरुक होना

इस बार गर्मी ने जो रंग दिखाया उससे वास्तव में सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। सूर्य की तपिश में मानों हर जीव झुलस रहे हों। नदियों का पानी सूखने की कगार पर आ गया। यहां तक कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल सूख गए, पोखर, तलाब सूख गए। कुंआ का अस्तित्व तो विलुप्त ही है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कभी पानी की किल्लत होती ही नहीं थी। इस बार वो भी क्षेत्र बिन पानी सून है। सूर्य की तपिश ऐसी की मानों जला ही दें और हुआ भी यही की इसबार हीटवेव के कारण कितनों की जानें चली गई। अधिकांश जगहों पर तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये सामान्य सी घटना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय है। आने वाले 10 साल में स्थिति ऐसी ही रही तो ये कहना गलत नहीं होगा की आसमान से आग बरसेगी और ये सिलसिला बढ़ता ही रहा तो आने वाले 40-50 साल में पूरा देश पानी की समस्या से जूझ रहा होगा और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा। तब की स्थिति की कल्पना ही भयभीत करती है।

आने वाले समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। नदियां प्रदूषण मुक्त हो जाएगी ऐसी बातें करना ही मूर्खतापूर्ण है। हम भौतिक सूखों में प्रकृति को भूलते जा रहे है। पर्यावरण संरक्षण की बातें बस पर्यावरण दिवस पर ही सुनने को मिलती है। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास इन विषयों पर सोचने के लिए समय ही नहीं है। कम से कम आने वाले वक्त के लिए तो अभी से कमर कस ही लेनी चाहिए कि अन्न-जल के अभाव में मरना है। अगर हम बच भी गए तो आने वाली पीढ़ी इसका दंश झेलेगी ही झेलेगी। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत रहा है। 2070 तक भारत की आधी आबादी सूर्य की तपिश और पानी के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहा होगा।

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकाला जा रहा है। इससे पृथ्वी की धुरी प्रभावित हुई है। साथ ही इसके घूमने का संतुलन भी बिगड़ा है। जल विशेषज्ञों ने लंबे समय से भूजल के अत्यधिक उपयोग के परिणामों के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। हमारी बड़ी लापरवाही से भूजल के स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अब समय आ चुका है कि हम सभी पर्यावरण के प्रति जितना सतर्क हो जाएं, उतना बेहतर। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए लोगों को भी जागरुक होना पड़ेगा। सरकार के साथ समाज को भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ खुद के लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए खुद से भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

निवाड़ी जिपं सीईओ रोहन सक्सेना सम्मानित, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नवाजा

भोपाल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निवाड़ी जिला पंचायत के सीईओ रोहन सक्सेना को वर्ष 2023 के दौरान चुनावों के संचालन के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। दिल्ली के मानेकशां सेंटर में गुरुवार को आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहन सक्सेना को मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया। सक्सेना ने निवाड़ी जिले के लिए 100 दिनों की स्वीप कार्यक्रम रणनीति बनाई जिसके तहत महिलाओं, युवाओं, पहली बार के मतदाताओं और प्रवासी श्रमिकों के लिए मतदाता भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित की गई। सीईओ के प्रयासों से निवाड़ी जिले में 2018 विधानसभा निर्वाचन की तुलना में 2023 के चुनावों के कुल मतदान में 5.10 फीसदी की वृद्धि हुई।

बारिश में बह गया है स्टॉप डैम

दो गांव के सैकड़ों किसानों के सामने पानी का संकट

दमोह। जागत गांव हमार

जिले के तारादेही और शिवलाल खमरिया गांव के बीच से बहने बाली व्यारमा नदी का है। जहां, 15 वर्ष पूर्व जलसंसाधन विभाग ने पानी रुकने के लिए नदी के बीचों बीच एक स्टॉप डैम बनवाया था। स्टॉप डैम निर्माण के बाद पानी काफी मात्रा मे रुक जाता था और नदी के आजू बाजु लगे दो गांव के किसानों को सिचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था, लेकिन इस वर्ष नदी के तेज बहाव में यह स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण पानी इस व्यर्थ बह रहा है। किसानों को इस वर्ष तो पानी मिल जायेगा, लेकिन यदि स्टॉप डैम की मरम्मत नहीं हुई तो अलगे वर्ष तक यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है और पानी रुकना मुश्किल हो जायेगा। यदि पानी नहीं रुका तो किसानो के खेतों मे होने बाली फसल की सिंचाई होनी बंद हो जायेगी। इसलिये दोनों गांव के किसान यही मांग कर रहे है कि गर्मियों के दिनों मे यदि स्टॉप डैम की मरम्मत का कार्य हो जाता है तो अगले वर्ष भी उनको पानी मिल जायेगा नहीं तो काफी परेशानी होगी।

ये बोले जिम्मेदार- व्यारमा नदी में बन स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हो गया है। इसको लेकर शिवलाल खमरिया के सरपंच देसराज सिंह लोधी ने बताया कि व्यारमा नदी पर जो स्टॉप डैम बना था, वह 2007, 2008 में बनाए गया था। स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हो गया है आजू-बाजू से इसकी दीवारें फूट गई हैं और बीच से भी दरारें आ गई हैं। इस वर्ष तो पानी रुका हुआ है, लेकिन यदि सुधार या मरम्मत नहीं होती है तो अगले वर्ष यह स्टॉप डैम पूरी तरह फूट जाएगा और पानी रुकना मुश्किल हो जाएगा।

डैम काफी पुराना

स्टॉप डैम से तारादेही और शिवलाल खमरिया के किसानों को अभी तक सिंचाई के लिए पानी मिलता था जो शायद अगले वर्ष न मिले। स्टॉप डैम जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया था और काफी पुराना हो चुका है।

- स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हो गया है, इसकी जानकारी मुझे है। पूर्व पदस्थ अधिकारियों द्वारा मरम्मत के लिए पत्राचार किया गया था, लेकिन ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। एक बार फिर उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में पत्राचार करके अवगत कराया जाएगा जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

राहुल जैन,एसडीओ,
जल संसाधन विभाग

खाद सही रेट पर मिले बिजली और फसलों के भाव भी सही मिले

-एमपी सहित देशभर के किसानों को केंद्रीय बजट से उम्मीद

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार का बजट एक फरवरी को आने वाला है। इस बजट से किसानों को भी कई उम्मीदें लगी हैं। वहीं इस बारे में मप्र के किसानों की राय जाना गया। यहां के किसानों ने बताया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए फसलों का भाव ठीक मिलना चाहिए। आम की फसल का रेट सही मिल जाए। किसान ने कहा कि इस बार किसानों को बहुत परेशानी हुई है साथ ही बहुत नुकसान भी हुआ है। खाद सही रेट में मिल जाए, बिजली सही मिल जाए और फसलों के भाव सही मिल जाए। सरकार जो अभी किसानों को दे रही है, वह ठीक-ठाक है। पिछली बार सरसों का रेट सही नहीं मिल पाया था, गेहूं के तो रेट ठीक हैं। इस बार उम्मीद है कि सरसों का रेट सही होगा। किसानों का कहना है कि आवारा पशु भी बहुत परेशानियां पैदा कर रहे हैं। किसानों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसके बदले पैसा मिलना चाहिए, उनका कहना है कि किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार सरकार किसानों के लिए राहत देगी। किसानों को मिलने वाली फसल की दवाइयां के रेट कम होने चाहिए। गेहूं के रेट बढ़े हैं 2275 का रेट था वह ठीक है। वहीं किसान की फसल के हर साल पैसे बढ़ाने चाहिए। खाद की तो कीमत बढ़ जाते हैं, लेकिन फसलों पर पैसे नहीं बढ़ते, जानवर फसलों को बर्बाद कर देते हैं इस पर रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को परेशानी है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही कीटनाशक और दवाइयां बढ़े हुए रेट पर मिल रही हैं उनके दाम कम होने चाहिए।

25 वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, नरसिंहपुर के प्रशिक्षण सभागार में 25 वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. दिनकर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता एवं जिलें के वरिष्ठ प्रगतिषील कृषक श्री चंद्रषेखर तिवारी एवं छिदवाड़ा जिलें से आए उन्नत कृषक रामदास सूर्यवंशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गयी। इस बैठक का मुख्य उद्देष्य कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्ष 2023-24 में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं वर्ष 2024-25 में संस्था के द्वारा जिले में कृषि की उन्नति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर चर्चा करना था ताकि कृषि से जुड़े अन्य विभागों जिले के प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति में गहन विचार विमर्श पश्चात कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु अंतिम स्वरुप प्रदान किया जा सके, इस बैठक में संस्था प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. विशाल मेश्राम दवारा बैठक का उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर द्वारा कृषकों के हित में चलाई जा रही गतिविधियों आगामी कार्यक्रमों का पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से वाचन किया गया। संस्था के

पौध संरक्षण वैज्ञानिक, डॉ. एस. आर. शर्मा द्वारा पौध संरक्षण के लिए तैयार किए गए प्रक्षेत्र परीक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा की गयी, वैज्ञानिक, कृषि वानिकी, डॉ. आशुतोष शर्मा द्वारा कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी पर बनाए गए कार्यक्रमों पर डॉ. विजय सिंह सूर्यवंशी सस्य विज्ञान के द्वारा उन्नत प्रजातियों के बीज उनकी उपलब्धता तथा उन्नत खेती पर चर्चा एवं डॉ प्रशांत श्रीवास्तव कृषि अभियांत्रिकी द्वारा कृषि में उन्नत यंत्रो का प्रयोग उनके रख रखाव व रेस्ड बेड द्वारा चने, सोयाबीन की बुवाई का तरीका फायदे पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस बैठक में उपस्थित सहायक संचालक उद्यान दिनेश कौतू, परियोजना उपसंचालक आत्मा, शिल्पी नेमा, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी डॉ. रामनाथ पटेल, सहायक संचालक दिप्ती यादव, सहायक संचालक डॉ रष्मि ठाकुर, सहायक संचालक कृषि अभियांत्रकी, यू.बी. सिंह आदि ने अपने-अपने विभागों के सुझाव प्रस्तुत कियें। उपसंचालक पशुपालन डॉ मोहम्मद असगर ने कृत्रिम गर्भाधान में नयी तकनीक जिससे गर्भाधान पश्चात् मादा पशुओं के ही जन्म पर चर्चा की गयी तथा केंद्र के दवारा पशुपालको, गौशालाओं को हरा चारा नेपियर घास की खेती हेतु प्रदाय किए गए कटिंग स्लिप्स पर ध्यानाकर्षण कराया गया इफ्को क्षेत्र अधिकारी, अजय प्रताप सिंह ?द्वारा नैनो यूरिया नैनो डी.ए. पी. के प्रयोग उसके फायदे पर चर्चा की गयी. प्रगतिशील कृषकों राकेश दुबे, राव गुलाब सिंह, कृष्णपाल सिंह लोधी, संजय वर्मा, मुकेष नेमा, अमित सोनी, स्वदेष कोठारी, अन्नीलाल पटैल ने जिलें में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम बनाये जाने की अनुषंसा की। शक्ति पूजा कृषक उत्पादक संगठन के सी.ई.ओ. श्री जगदीष मेहरा द्वारा समूह की दीदीओं को संस्था द्वारा प्रदाय किये गये अरहर की उन्नत प्रजाति जी.आर.जी. 152 (भीमा) और मसूर की उन्नत प्रजाति एल. 4717 के उन्नत उत्पादन पर प्रकाष डाला गया। कार्यक्रम के अंत में सभी आए हुये अतिथियों द्वारा केन्द्र के प्रक्षेत्र, फसल संग्राहलय एवं विभिन्न ईकाईयों का भ्रमण किया गया एवं अपने सुझाव प्रदाय किये गयें।

18 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, आपराधिक घटनाओं पर लगेगी लगाम

हाईटेक बनी बुंदेलखंड की ग्राम पंचायत चंद्रपुरा

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी सहित अपराध तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बल्देवगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत चंद्रपुरा में पंचायत की ओर से नई पहल शुरू की गई है। पंचायत सरपंच विदेह पाठक ने बताया कि गांव में महिला सुरक्षा और नशाखोरी की वारदातों को रोकने के लिए पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा गया है। गांव के प्रमुख चौराहों और रास्तों पर कुल 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजीव पाठक ने बताया कि गांव में लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे वायरलेस सिस्टम से

लगाए गए हैं। प्रत्येक में दो कैमरे लगे हैं। यानी 18 सीसीटीवी कैमरों से 36 एंगल कवर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी मोबाइल फोन पर की गई है। ताकि घर बैठे गांव में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी को थाने से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के रामचरण ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लग जाने से गांव में अपराध घटेंगे। इसके अलावा नशा करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से गांव में सुरक्षा का माहौल हो गया है।

सीवेज सिस्टम से सुर्खियों में आया था गांव

इसके पहले ग्राम पंचायत चंद्रपुरा में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम तैयार किया गया। गांव की सभी खुली नालियों को अंडर ग्राउंड बनाकर ऊपर से ढंक दिया गया है। सीवेज सिस्टम के पूरे पानी को गांव के अंत में चेंबर बनाकर छोड़ा जा रहा है। जिस गांव साफ और स्वच्छ दिखने लगा है। लोगों को खुली नालियों से छुटकारा मिला है।

ब्याज की राशि से लगाए कैमरे

सरपंच पति संजीव पाठक ने बताया कि पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए फिलहाल कोई अलग से बजट नहीं है। न ही शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गांव के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 2 लाख रुपए की लागत से 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के खाते में जो राशि है, उसके ब्याज से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

40 प्रतिशत सब्सिडी देगी राज्य की मोहन सरकार

अब खेतों में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे अन्नदाता

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलेंगी, क्योंकि अब किसानों को अपनी फसलों में कीटनाशक दवाए डालने में समस्याओं का सामना नही करना पड़ेगा। खेतों में दवाओं का छिड़काव करने में अधिक लागत आती है। इसके साथ ही कीटनाशक के संपर्क में आने का जोखिम भी रहता है। इन समस्याओं को दूर करने और समय बचाने कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का उपयोग करने की तैयारी हो गई है. अब नर्मदापुरम जिले में खेतों के ऊपर जल्द ही ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। अब ड्रोन को फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करने मेंउपयोग किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने विकसित भारत यात्रा के दौरान जिले के 150 गांव में ड्रोन का डेमो देकर किसानों को जानकारी दी है। किसानों के लिए ड्रोन कीटनाशकों के छिड़काव के साथ चौकीदारी का काम भी करेगा। ड्रोन के जरिए किसान लंबे खेतों की मॉनिटरिंग भी असानी से कर सकते हैं। ड्रोन से दवा के टैंक को निकालकर उसमें कैमरे लगाने के व्यवस्था रहेगी। किसान कैमरे की मदद से एक जगह बैठे ही अपने खेत पर निगरानी रख सकते हैं। ड्रोन के डेमो के समय कृषि विभाग ने किसानों को बताया कि खेतों में ड्रोन से किस तरह छिड़काव करना है। इसके साथ ही इससे होने वाले विभिन्न फायदे भी बताएं गए हैं। खेतों में ड्रोन उड़ाने के लिए किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को विभाग भोपाल, इंदौर के कौशल विकास केंद्रों के जरिए पायलट की ट्रेनिंग देगा।

किसानों को मिलेगी सब्सिडी

उप संचालक कृषि जेआर हेडउ ने बताया कि नर्मदापुरम जिले के 150 गांव में डेमो देकर किसानों को ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। फरवरी से किसानों को 10 लाख के ड्रोन के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें 40 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिलेगी। जिले के किसानों को ड्रोन को खरीदने के लिए विभाग लोन देगा। 10 से 16 लीटर कीटनाशक एक साथ ले जाने की क्षमता वाले 10 लाख रुपए के ड्रोन को खरीदने विभाग किसान को लोन देगा। किसानों को इसमें 40 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि फरवरी माह से कृषि विभाग के पोर्टल पर स्कीम शुरू कर दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के साथ किसानों को ड्रोन मिलना शुरू हो जाएंगे। किसानों को ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस भी दिया जाएगा।

खरीदी केंद्र परिसर में वाहन में रखे धान को किया जब्त

अनूपपुर। जागत गांव हमार

जिले में धान खरीदी का कार्य बंद है, इसके बाद भी कोतमा में ट्रक वाहन में 121 बोरी धान खरीदी केंद्र परिसर में रखे हुए पाए जाने पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर ट्रक वाहन को जब्त करते हुए मामले की जांच की जा रही है। मामले के संबंध में बताया गया कि वाहन क्र. एमपी 18 जीए 1550 जिसमें 121 बोरियों में लगभग 49 क्विंटल 40 किलो धान रखा हुआ था, जोकि खरीदी केंद्र परिसर में ही खड़ा था। जिसमें गड़बड़ी की आशंका को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के पश्चात जांच की जा रही है। जब्त किए गए वाहन तथा उसमें रखे हुए धान के संबंध में बताया गया कि 25 जनवरी को रेउला राइस मिल से धान का परिवहन करते हुए खरीदी केंद्र तक लाने के लिए खरीदी केंद्र प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी के निर्देश पर वाहन चालक सुदामा अवधिया के द्वारा उक्त धन को राइस मिल से लाया गया। 25 जनवरी को गोदाम लाने के दौरान शाम होने के कारण बंद हो जाने पर वाहन चालक के द्वारा धान को खरीदी केंद्र परिसर में ही खड़ा कर दिया गया।

गड़बड़ी की आशंका

26 जनवरी को छुट्टी हो जाने के कारण भी गोदाम नहीं खुल पाया और 26 जनवरी को भी वाहन खरीदी केंद्र परिसर में ही खड़ा था, तभी गड़बड़ी की आशंका को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा इसकी शिकायत एसडीएम से की गई। जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पटवारी तथा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई पूर्ण होने तक वाहन को थाना परिसर की अभिरक्षा में खड़ा करा दिया।

181 क्विंटल का ही डीओ प्राप्त हुआ

इस मामले पर खरीदी केंद्र प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर धान को राइस मिल से गोदाम तक लाया जा रहा था। 230 क्विंटल धान विभाग के निर्देश पर मिलिंग के लिए राइस मिल भेजा गया था, जिसमें राइस मिल को 181 क्विंटल का ही डीओ प्राप्त हुआ। शेष 49.4 0 क्विंटल धान को वहां से वापस लाने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के पश्चात इसे लाकर के परिसर में गोदाम का ताला बंद होने के कारण रखा गया था।

अब मालामाल हो रहे किसान, दुनियाभर में बन रही पहचान

जिले के दो लाख 80 हजार किसानों ने बोवनी का लक्ष्य पूरा किया

सोना उगल रही नर्मदांचल की माटी

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले की धान की महक देशभर में फैल रही है। प्रोटीन युक्त यहां के गेहूं की एमपी के साथ ही यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी मांग रहती है। उप संचालक कृषि जेआर हेडऊ ने बताया कि जिले में गेहूं की उत्पादकता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। सिंचाई के लिए पानी मिलने के कारण गेहूं उत्पादन में जिले के किसानों को भरपूर लाभ हो रहा है। नर्मदा, तवा जैसी नदियों से घिरे नर्मदाचंल की धरती पर सोने की चमक वाला गेहूं किसानों को मालामाल कर रहा है। इसका कारण यहां की जिले की जमीन उपजाऊ होना है। नर्मदापुरम जिले में इस साल 2,45,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में गेहूं की बोवनी के लिए 246.80 हजार हेक्टयर का लक्ष्य तय किया गया था। जिसमें अभी तक 242.14 हजार हेक्टयेर में बोवनी की गई। इस तरह जिले के 2 लाख 80 हजार किसानों ने बोवनी का लक्ष्य पूरा किया है।

चना की तरफ बढा रुझान

इस बार जिले में चना का उत्पादन भी बेहतर हो रहा है। वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग ने जिले में 70 हजार हेक्टेयर में चना की बोवनी का लक्ष्य तय किया था। इसमें 77.58 हजार हेक्टेयर में बोवनी कर 110 प्रतिशत लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है।

चार साल में गेहूं उत्पादन

2018-19	1350.62 एमटी
2020-21	1461.82 एमटी
2021-22	1370.50 एमटी
2022-23	1310.60 एमटी

पर्याप्त मिल रहा पानी

नर्मदापुरम जिले में गेहूं और चना की सिंचाई के लिए तवा बांध से 1,000 मिलियन क्यूविक मीटर पानी 2,000 हजार किलोमीटर की नहरों में छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके हिसाब से नहरों में प्रतिदिन 4,311 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे जिले की 1 लाख 60 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। इसके साथ ही किसान अपने निजी जल स्त्रोतों से भी सिंचाई करते हैं।

महाकोशल में पहली बार राजमा की खेती

ढाई एकड़ में ढाई लाख की होगी कमाई खेती देखने दूसरे किसान भी पहुंच रहे

ऋषिराज गोटिया से जानें राजमा की खेती शुरू करने की कहानी

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर नई फसल की खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती जहां किसानों की आय बढ़ा रही है, वहीं ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले लागत और मुनाफे के अंतर को खत्म कर रही है। ऐसे ही जबलपुर के एक किसान हैं, जो ढाई एकड़ में राजमा की खेती कर रहे हैं। जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा होने का अनुमान है। राजमा की खेती करना वाला जबलपुर प्रदेश का दूसरा संभाग भी बन गया है। इससे पहले मालवा अंचल में दो साल से राजमा की खेती हो रही है। जागत गांव हमार अपने इस अंक में किसानों का मिलवा रहा है जबलपुर के शहपुरा में रहने वाले किसान ऋषिराज गोटिया से। ऋषिराज के पास करीब 10 एकड़ जमीन है। जिसमें वो गेहूं, धान, मसूर या मटर की खेती करते हैं। कुछ दिन पहले ऋषिराज घूमने के लिए नीमच और खरगोन गए थे। जहां उन्होंने राजमा की खेती देखी। जबलपुर संभाग में इससे पहले किसी ने राजमा की खेती नहीं की थी। फिर अपने भांजे की सलाह पर उन्होंने भी खेती शुरू की। अब दूसरे किसान भी खेती देखने पहुंच रहे हैं।

जबलपुर संभाग में पहली बार राजमा की खेती कर रहा हूं। जिस तरह से बीज लगाए हैं, उसको देखते हुए उम्मीद है कि फसल के साथ इनकम भी अच्छी होगी। खेती शुरू करने से पहले नीमच-खरगोन के किसानों से राजमा की खेती की बारिकियों को समझा। फिर मुझे पता चला कि उत्तराखंड में राजमा की खेती होती है। जिसके बाद उत्तराखंड के एक किसान से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की। जब मैं उनसे राजमा की खेती के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गेहूं, धान से अच्छा प्रॉफिट हमें राजमा की खेती में होती है। परंपरागत खेती की अपेक्षा इसमें लागत के साथ-साथ मेहनत भी कम लगती है। उत्तराखंड के दोस्त ने ही मुझे अच्छे किस्म की बीज उपलब्ध करवाया। एक एकड़ में 8 से 14 क्विंटल तक राजमा की पैदावार होने का अनुमान है। जिसमें मुझे ढाई लाख रुपए तक मुनाफा होने की उम्मीद है।

सीहोर में मेरा भांजा सुनील दो साल से राजमा की खेती कर रहा है। उसने 2021-22 में ढाई एकड़ जमीन में राजमा की फसल लगाई थी। पहली बार बीज 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल खरीदे थे। इसके अलावा 2 हजार खाद, 1800 की दवाई और 8000 रुपए कटाई लगी थी। कुल मिलाकर करीब 42 हजार रुपए खर्च आया था। जिसमें आमदनी कम से कम 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल होती है, जो बढ़कर 18000 रुपए तक पहुंच सकती है। पहली बार सुनील ने ढाई लाख रुपए की कमाई की थी।

दूसरे किसान कर हो रहे प्रेरित

जब जागत गांव हमार की टीम उनके पास पहुंची थी। उसी समय शहपुरा के ही किसान अशोक कुमार अपने साथियों के साथ राजमा की खेती देखने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि ऋषिराज राजमा की खेती कर रहे हैं। महाकोशल में पहली बार हो रही है, इसलिए देखने आए हुए हैं। अगर राजमा की खेती में ज्यादा मुनाफा होता है तो अगले सीजन में गेहूं, धान को छोड़कर राजमा की ही खेती करेंगे।

ऐसे समझें परंपरागत और राजमा की खेती में अंतर

गेहूं की फसल तैयार होने में 140 से 160 दिन लगते हैं। इसी तरह से धान की फसल में 120 से 150 दिन, वहीं मटर की फसल भी 120 दिन में तैयार होती है। जबकि राजमा की फसल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। राजमा की फसल को सिर्फ तीन से चार बार पानी देना होता है। गेहूं और धान के मुकाबले एक तिहाई कम है। राजमा की फसल आने के बाद उसे दो साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। वर्तमान में राजमा का बाजार भाव 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। राजमा के लिए 12-32-16 खाद सबसे अच्छी मानी जाती है, इसके लिए डीएपी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह महंगी होती है। इसके अलावा सुपर फास्फेट और स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

साल में 2 से 3 बार लिया जा सकता है फसल

कृषि विस्तार अधिकारी रजनीश दुबे ने बताया कि पहली बार किसान ऋषिराज गोटिया ने राजमा की खेती शुरू की है। यह एक दलहनी फसल है। जिसके दाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बाजार में इसकी हमेशा मांग रहती है। जबलपुर संभाग में अभी राजमा की फसल नहीं की जा रही थी, शहपुरा विकासखंड के किसान का यह पहला प्रयास है। राजमा फसल को साल में दो या तीन बार लिया जा सकता है। इस फसल में कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। कृषि विभाग ने भी किसानों को राजमा की खेती करने की सलाह दी है।

ऐसे करते हैं राजमा की खेती

राजमा की खेती करने के लिए अच्छी किस्म की बीज की आवश्यकता होती है। साथ ही कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होती है। इसके साथ ही अगर मिट्टी की जांच करवाकर इसकी खेती की जाए तो पैदावार काफी ज्यादा हो सकती है। कई जगह इसे फरवरी में भी बोया जाता है और बारिश शुरू होने से पहले फसल तैयार हो जाती है। दूसरी फसलों की तुलना में राजमा से ज्यादा आमदनी होती है और कई बार तो कटाई के दिन फसल बिक जाती है।

असम के चिरांग के रहने वाले सर्वेश्वर अपने क्षेत्र में चिंराग के चिराग के नाम से प्रसिद्ध

कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए तीन किसान और दो पूर्व वैज्ञानिकों को पद्मश्री

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के गौरव और प्रगति में अहम योगदान देने वाले नागरिकों को पद्मश्री अवॉर्ड दिए गए हैं। इसमें से कई ऐसे किसान भी शामिल हैं जिन्होने खेती का स्तर सुधारने और अन्य किसानों का जीवन बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। ऐसे ही तीन किसानों और दो कृषि वैज्ञानिकों को पद्मश्री पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए पद्मश्री पुरुस्कार पाने वालों में केरल के बेल्लूर में रहने वाले किसान सत्यनारायण बेलरी भी शामिल हैं। वो धान की किस्मों का संरक्षण करते हैं और 2008 के बाद से 650 से ज्यादा किस्मों को संरक्षित कर चुके हैं। उनकी कोशिश की वजह से कई किस्मों को लुप्त होने से बचाया गया है। सिर्फ 12वीं पढ़े इस किसान की मदद अब वैज्ञानिक और कृषि संस्थान तक ले रहे हैं। वहीं के चेल्लामल को नारियल अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान में रहने वाली चेल्लामल को पद्मश्री का अवॉर्ड हासिल हुआ है। वह जैविक कृषि के जरिए कई फसलों को न केवल उगा रही

हैं। साथ ही कई किसानों के इस तरह खेती करने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। वो लगातार इनोवेशन कर रही हैं जिससे कम लागत पर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खेती की जा सके। वो सिर्फ छठी कक्षा तक ही पढ़ी हैं। असम के चिरांग के रहने वाले सर्वेश्वर अपने क्षेत्र में चिंराग के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो पहले एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन कृषि की ओर लौटकर एक सफल किसान बने। उन्होंने खेती के लिए ऐसे तरीके खोजे जिसने आय बढ़ाने में मदद की है। अब वो युवाओं को किसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने अनुभव और जानकारी को उनके साथ बांटते हैं जिससे ये युवा खेती में सफलता पा सके और अपनी कमाई को और बेहतर बना सकें।

हरियाणा के दो वैज्ञानिकों को अवार्ड

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, हिसार के दो पूर्व वैज्ञानिकों डॉ. हरिओम व डॉ. रामचंद्र सिहाग का चयन पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है। डॉ. हरिओम ने प्राकृतिक खेती और डॉ. रामंचद्र सिहाग ने मधुमक्खी पालन विषय पर बेहतरीन काम करके किसानों को फायदा दिलाया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने हजारों किसानों को न सिर्फ ट्रेंड किया, बल्कि उनके स्वरोजगार इकाई को स्थापित करने में भी अपनी अहम भूमिका अदा की। डॉ. हरिओम ने 36 साल तक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, हिसार में अपनी सेवाएं दीं। प्रो. रामचंद्र सिहाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद् हैं। उन्होंने नवंबर 1979 से जनवरी 2012 तक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, हिसार में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

सीएम ने की घोषणा-उज्जैन में बनेगी मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी

श्री अन्न उत्पादक किसानों को एक हजार क्विंटल प्रोत्साहन देगी सरकार

उज्जैन। जागत गांव हमार

गणतंत्र दिवस को लेकर उज्जैन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की। साथ ही प्रदेश की कई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर सहित अन्य शहरों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सफाई मित्रों की तारीफ की। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की जेल में बंद 161 कैदियों को रिहा करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य की संकल्पना जीवंत हो गई है। उन्होंने घोषणा की कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां प्रतिवर्ष रामायण मेला आयोजित किया जाएगा। साथ ही मप्र सरकार सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई और रेल मार्ग से अयोध्या की यात्रा कराएगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न उत्पादन में क्रांति लाने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है । श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक हजार रुपए प्रति क्विंटल राशि का भुगतान किया जाएगा।

खाते में जमा किए 1576 करोड़- सीएम ने कहा कि पीएम के आह्वान पर 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण और युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति पर उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में 1576 करोड़ की राशि और 56 लाख हितग्राहियों के खाते में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई।

सीएम की अन्य बड़ी बातें

- उज्जैन में मेडिसिटी बनाई जाएगी। जिसके निर्माण से सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यह प्रदेश की पहली मेडिसिटी होगी।
- सरकार ने मध्य प्रदेश के इतिहास की सर्वाधिक 17 हजार 586 मेगावाट बिजली की पूर्ति बिना किसी कटौती के की है।
- पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से 136 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बचत की संभावना।
- पांच शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है। उज्जैन में कपिला गौशाला के लिए योजना बनाई जाएगी।
- मप्र दाल उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
- मोबाईल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से 3 लाख 60 हजार पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के 50 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)